www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

सत्यमेव जयते

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खण्ड 38 अंक 50 पृष्ठ 56 | नई दिल्ली 15 - 21 मार्च 2014 | ₹ 8.00

ब्रिक्स: संभावनाएं एवं चुनौतियां

प्रोतिवा कुंडु

2001 में, अमरीकी बैंक गोल्डमैन सैचस के मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने ''बेहतर वैश्विक अर्थव्यवस्था ब्रिक का निर्माण'' पर एक रिपोर्ट में पहली बार 'ब्रिक' वाक्यांश को चुना था, जिसका आशय उस वक्त विश्व की तेज़ी से अग्रसर और उभरती अर्थव्यवस्थाओं अर्थात ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन से था. जनसंख्या के आकार, जनसांख्यिकीय लाभांश और वैश्वीकरण की दर जैसी विशेषताओं की तरफ ध्यान देते हुए गोल्डमैन सैचस ने अनुमान व्यक्त किया कि इन चार देशों में बाज़ार के आकार की दृष्टि से यूरोपीय अर्थव्यवस्था का स्थान लेने की विकास क्षमता है. उन्होंने यह अनुमान भी व्यक्त किया कि चीन, भारत, ब्राज़ील और रूस वर्ष 2050 तक क्रमशः पहली, तीसरी, चौथी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हो जायेंगी. यद्यपि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर 'ब्रिक' की औपचारिक तौर पर पहली शुरूआत ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सितंबर, 2006 में हुई बैठक के दौरान मुलाकात से हुई थी. बाद में अप्रैल 2011 में (तीसरे ब्रिक सम्मेलन) दक्षिण अफ्रीका इस मंच में शामिल हो गया और 'ब्रिक्स' का गठन हो गया.

पांच देशों का एक साथ मिलाकर यह विश्व जनसंख्या का 43 प्रतिशत, वैश्विक श्रम बल का 46 प्रतिशत, धरातल का 30 प्रतिशत और दुनिया के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 25 प्रतिशत हिस्सा बनता है. ब्रिक्स देश संसाधनों के आदान-प्रदान से अपनी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं में योगदान करने के साथ-साथ औद्योगिक जगत के लिये भी प्रमुख संसाधन आपूर्तिकर्ता बने हुए हैं. यद्यपि इन देशों में सांस्कृतिक और राजनीतिक समानता बहुत कम है और उनके विकास के स्तरों में भी व्यापक अंतर है. इन देशों के बीच पहले कोई महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी नहीं होने पर भी ब्रिक्स का सृजन वैकल्पिक आर्थिक दायरे के तौर पर एक प्रमुख कदम था. ब्रिक्स के सृजन के मूल में सदस्य राष्ट्रों के दीर्घावधि संयुक्त आर्थिक हित शामिल थे जिनमें वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संरचना में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और मानदंडों को सुदृढ़ करना और उनकी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में समानताओं को समर्थन करना शामिल है.

उद्देश्य

ब्रिक्स की कार्यसूची का क्षेत्र बहुत व्यापक है. हालांकि इसकी शुरूआत 2008-09 की वैश्विक आर्थिक मंदी पर नियमित और सघन विचार-विमर्श के साथ हुई थी, लेकिन इसकी कार्यसूची में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक व्यापारिक आर्डर, सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी), अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संस्थानों में सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक घटनाक्रम जैसे मामलों को भी शामिल कर लिया गया.

ब्रिक्स सम्मेलन

मंच के तौर पर ब्रिक्स का प्रचालन 2009 में ही हुआ है और मात्र पिछले एक दो सालों में ही यह विकास क्षेत्रों में बढती रुचि का विषय बना है. ब्रिक्स के कार्यक्रम में विदेश मंत्रियों और वित्त मंत्रियों की नियमित बैठकें विशेष महत्व रखती हैं. इसके अलावा बीते कुछ वर्षों में ब्रिक्स देशों के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने के वास्ते कई तंत्र विकसित किये गये हैं. उदाहरण के तौर पर सदस्य राष्ट्रों के व्यापार, वित्त, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि मंत्रियों की बैठकों का आयोजन किया गया है.

पहला ब्रिक सम्मेलन 2009 में रूस के येकातरिनबर्ग में हुआ था. दूसरा सम्मेलन 2010 में ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित किया गया. 2011 में चीन के सानया में तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, जिसमें मंच ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार के लिए मांग उठाई और ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के जरिए सहयोगात्मक कार्य हेतु सांस्थानिक तंत्र कायम करने पर ध्यान केंद्रित किया. सम्मेलन में कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया. चौथा सम्मेलन 2012 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां ब्रिक्स देशों ने ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास से जुड़ी विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिये एक बहु आयामी विकास बैंक की

शेष पृष्ठ 56 पर

रोज़गार सारांश

क.च.आ.

- कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप-निरीक्षक एवं के.औ.सु.ब. में सहायक उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा 2014 का आयोजन. रिक्तियां : 2892

अंतिम तिथि: 11.04.2014

एन.सी.एल.

- नोर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरोली को 2311 स्टाफ नर्स ग्रे. सी., माइनिंग सरदार ग्रे. सी., आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी वर्ग-III, एचईएमएम ऑपरेटर ट्रेनी वर्ग-II आदि की आवश्यकता.

अंतिम तिथि: 31.03.2014

कृ.वै.च.मं.

- कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक पदों के लिए आवेदन आमंत्रितं

अंतिम तिथि: 31.03.2014

भा.रा.रा.प्रा.

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 83 उप महाप्रबंधक, प्रबंधक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 16.04.2014

आई.आर.ई.एल.

- इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड को 52 ट्रेड्समेन और हैल्पर-बी की आवश्यकता.

अंतिम तिथि: 31.03.2014

वेब विशेष

www.rojgarsamachar. gov.in पर वेब विशेष खण्ड के तहत निम्नलिखित आलेख उपलब्ध हैः-

1. चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोत्तरी

आपदा प्रबंधन-एक शानदार कॅरिअर

डॉ. अशोक जी. मतानी

28 फरवरी, 2013 : कोलकाता बाजार में लगी आग में 21 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 6 व्यक्ति घायल

16 जून, 2013 : आकस्मिक बाढ़ से 5700 लोगों के मारे जाने का अनुमान

24 अगस्त, 2013 : विजाग एच.पी.सी.एल. अग्निकांड में 24 व्यक्तियों की जाने गईं

14 अक्टूबर, 2013 : फैलीन चक्रवात में हजारों झोपड़ियां तथा कई एकड़ फसल बर्बाद

31 अक्टूबर, 2013 : हवरी वॉल्वो बस में लगी आग से 46 व्यक्तियों की मृत्यु

ये कुछ ऐसी भयंकर आपदाएं हैं, जो वर्ष 2013 में भारत में हुई. इन आपदाओं के कारण हुई जान-माल की हानि हमारे देश में आपदा प्रबंधन की तैयारी में अपर्याप्तता दर्शाती है. भारत एक सघन आबादी वाला देश है और यहां विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं. इन्हें देखते हुए, आपदा प्रबंधन लोगों के जीवन तथा देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यक है. इसलिए यदि आप समाज एवं देश के व्यापक हित के लिए कार्य करने की ललक रखते हैं तो आपदा प्रबंधन आपके लिए कॅरिअर का एक उपयुक्त विकल्प है.

आपदा प्रबंधन आपदाओं का सामना करने की योजना तथा प्रक्रियाओं से जुड़ा है. आपदाएं प्राकृतिक हो सकती है जैसे भूकम्प, सूखा और सुनामी या मानव रचित भी हो सकती है. जैसे युद्ध, बम विस्फोट तथा रासायनिक रिसाव आदि. आपदा किसी भी तरह की हो, इनमें जान-माल का नुकसान होता ही है. इससे भी अधिक जोखिम यह होता है कि समाज में लोगों के जीवन पर ये लम्बे समय तक अपना प्रभाव छोड़ती हैं. इसलिए आपदा प्रबंधन अत्यधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए. मानव जीवन के विविध आयामों को ध्यान में रखते हुए इसकी रूप रेखा बनाई जानी चाहिए तथा विकास किया जाना चाहिए.

यह किस बारे में है

आपदा प्रबंधन संभावित आपदाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने की नीतियां तैयार करने के कार्य से प्रारंभ होता है. इसमें ऐसी आकस्मिक योजनाएं तथा पद्धतियां निहित होती हैं जिन्हें आपदा आने पर होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कार्यान्वित किया जाता है. इसमें आपदा के बाद पुनर्वास शामिल है. यह आपात प्रबंधन के रूप में भी जाना जाता है और यह हमारा मार्गदर्शन करता है कि किसी आपदा के आने पर प्रभावित व्यक्तियों को श्रेष्ठ संभावित सहायता देने में संसाधनों तथा दायित्वों का किस तरह प्रबंधन किया जाए.

आपदा प्रबंधन एक व्यापक तथा गहन प्रक्रिया है जिसमें अनेक कार्य तथा उपाय शामिल हैं. इसलिए आपदा प्रबंधन दलों में विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि तथा कार्य अनुभव रखने वाले व्यवसायी होते हैं. उदाहरण के लिए जब कोई बाढ़ आती है, गैर सरकारी संगठन और सरकारी अधिकारी प्रभावित क्षेत्र को खाली कराने के लिए मिल कर कार्य करते हैं. प्रायः रक्षा कार्मिक बाढ़ से घिरे व्यक्तियों को बचाने का कार्य करते हैं. चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कर्मी शरणार्थी कैम्पों में बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए कार्य करते हैं. सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्वयंसेवी बचाए गए व्यक्तियों को बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति करते हैं. विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठन समाज के पुनर्निर्माण और प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास की दिशा में योगदान करते हैं.

अपेक्षित कौशल

इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मियों को संभार तंत्र एवं आपूर्ति श्रृंखला, सार्वजनिक स्वास्थ्य, संचार तथा ऐसे ही अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तर का ज्ञान एवं कौशल रखने की आवश्यकता होती है. चूंकि इस कार्य में अन्य अनेक व्यक्तियों के साथ समन्वय और सहयोग शामिल है, इसलिए मिल कर कार्य करने की क्षमता, अंतर वैयक्तिक कौशल, संचार कौशल तथा अन्य व्यवसायियों के योगदान के सम्मान की भावना होनी चाहिए. कुशाग्र-बुद्धि, समानुभूति, लोगों की सहायता करने की प्रतिबद्धता, विपरीत स्थितियों में रहने की क्षमता तथा परिश्रम करने की तत्परता होना महत्वपूर्ण है.

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य-भूमिकाएं विभिन्न होती हैं. कार्य के आधार पर जिम्मेदारियां आपदा प्रभावित व्यक्तियों को पुनः स्थापित करने से लेकर आपदा के बाद प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास, नीति बनाने, क्षेत्रगत प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, नुकसान का मूल्यांकन, उपयुक्त प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना, मानव संसाधन संग्रहण, गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकारी संगठनों के साथ समन्वय तथा प्रकाशन एवं प्रलेखन की होती है. इस क्षेत्र में कॅरिअर बनाने के इच्छुक छात्र अध्ययन के किसी एक संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं. आपदा प्रबंधन में कोई अल्पकालीन पाठ्यक्रम इस क्षेत्र से जुड़ा विशिष्ट ज्ञान तथा कौशल प्रदान कर सकता है.

रोज़गार के अवसर

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ कार्य भूमिकाएं इस प्रकार हैं: - परियोजना अधिकारी, एमरजेंसी रिस्पोंस मैनेजर, आपदा प्रबंधन अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, समाजविज्ञानी, अर्ध-चिकित्सा व्यवसायी, पर्यावरण विज्ञानी आदि. रोज़गार के अवसर सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में हैं.

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, भारतीय रेड क्रास सोसायटी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा राष्ट्रीय आपदा

शेष पृष्ठ 56 पर

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल.एसडब्ल्यू 1/4100/2012.14 यू. (सी.).107/2012.14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई. 28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 15/17.03.2014 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 13.03.2014

ब्रिक्स : ....

पृष्ठ 1 का शेष

स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने का निर्णय किया. पांचवां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के डरबन में मार्च 2013 में हुआ. इसका विषय था ''ब्रिक्स एवं अफ्रीका: विकास, एकीकरण और औद्योगिकीकरण के लिये साझेदारी. इस सम्मेलन में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय अफ्रीकी देशों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने, ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और व्यापार के विविधीकरण की प्रक्रियाओं के जरिए उनके औद्योगिकीकरण में मदद करने के बारे में था. मुख्य ज़ोर अफ्रीका में औद्योगिक विकास, रोज़गार सृजन, कौशल विकास, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के वास्ते बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने पर था.

ब्रिक्स नेताओं ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 2015 तक हासिल करने पर जोर दिया और कहा कि 2015 के बाद गरीबी उन्मूलन और मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमडीजी ढांचे का निर्माण किया जाना चाहिए. हालांकि ये आशंकाएं हैं कि गरीब विकासशील देशों के साथ ब्रिक्स के बढ़ते व्यापार और निवेश संपर्क से इन देशों के प्राकृतिक संसाधन आधार के दोहन के तरीकों से पारिस्थितिकी को हानि, स्वाभाविक असमानता के साथ स्थानीय लोगों को बहुत कम लाभ पहुंच रहा है.

ब्रिक्स समर्पित बैंक की स्थापना पर विचार-विमर्श पांचवे ब्रिक्स सम्मेलन में जारी रहा, परंतु इसमें संदेह है कि क्या ब्रिक्स वास्तव में इस विचार को मूर्त रूप दे पायेगा. जहां तक निवेश और व्यापार का संबंध है, इन देशों के बीच बहुत अधिक समानता नहीं है और सचिवालय के स्थान, अंशदान राशि, नियंत्रण एवं स्वामित्व तथा ऋण व्यवहार जैसे कुछ आधारभूत प्रश्नों का अभी समाधान किया जाना है. ब्रिक्स राष्ट्रों का उद्देश्य नये विकास बैंक में आरंभ में 50 अरब डॉलर का योगदान करने का है, परंतु इस बात पर असहमति थी कि क्या प्रत्येक देश को समान रूप से अंशदान करना चाहिए अथवा अपनी अर्थव्यवस्थाओं के आकार के अनुरूप अंशदान भिन्न हो. यद्यपि, यह जानते हुए कि चीन की अर्थव्यवस्था आकार के हिसाब से दक्षिण अफ्रीका से करीब 20 गुणा और रूस अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था से चार गुणा तक बढ़ी है, इस बात की संभावना है कि बैंक में चीन का प्रभुत्व रहेगा.

ब्रिक्स में भारत की स्थिति

भारत पर, इसकी जनसंख्या विशेषताओं, लोकतंत्र की मजबूती, व्यापक घरेलू बाज़ार, प्रौद्योगिकीय कुशाग्रता और निवेश क्षमता को देखते हुए मजबूत उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर व्यापक रूप से विचार किया जाता है. लेकिन देश की आर्थिक क्षमता का ब्रिक्स के अन्य सदस्यों के साथ तुलना हेतु एकमात्र दायर नहीं होना चाहिए. हालांकि भारत अन्य ब्रिक्स देशों के साथ कुछेक समान प्रकार की विशेषताएं रखता है, लेकिन वास्तव में इस समूह में इसकी विशिष्टता है जैसा कि ड्रेजे एंड सेन ने उल्लेख किया है. (2013). भारत का प्रति व्यक्ति जीडीपी (क्रय शक्ति समानता हेतु समायोजित) चीन से आधे से भी कम, रूस से एक चौथाई है. (ड्रेजे एंड सेन 2013). इस सेट में प्रत्येक देश ने सार्वभौमिकता अथवा सार्वभौमिकता के निकट की वयस्क साक्षरता दर हासिल कर ली है, इसमें भारत एकमात्र अपवाद है. इसी तरह अन्य देशों की तुलना में पूर्ण टीकाकृत बच्चों का अनुपात भारत में कम है. यद्यपि गरीबी और असमानता ब्रिक्स देशों में महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, भारत उच्च असमानता, कम उत्पादक रोज़गार और एक बड़े अनौपचारिक श्रम बाजार के साथ सबसे गरीब है.

ब्रिक्स में भारत की भूमिका

छठे ब्रिक्स सम्मेलन में, जो कि 2014 में फोटोलेजा, ब्राजील में होने जा रहा है (इस वर्ष जुलाई में आयोजित किये जाने की संभावना है), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के सुधार और विकास बैंक के सृजन की वर्तमान कार्यसूची पर विचार-विमर्श जारी रहेगा. समूह के आर्थिक सहयोग से बाहर निकलकर सहयोग बढ़ाने और अपने विचार-विमर्श की रेंज के विस्तार करने की भी संभावना है. भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति प्रति वर्ष 5 प्रतिशत से भी कम की आर्थिक वृद्धि के साथ थोड़ी निराशाजनक है. इसके मद्देनज़र प्रस्तावित विकास बैंक में भारत का वित्तीय अंशदान व्यापक तौर पर अनिश्चित है. इसके अलावा गरीबी, असमानता, सामाजिक अवसंरचना, कृषि और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को उठाकर भारत (इस मंच से) अपने लिये अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है. ब्रिक्स देशों के बीच उनके संपीड़क मुद्दों पर सहयोग और समन्वय से इन कुछेक चुनौतियों से निपटने में भारत की महत्वपूर्ण मदद हो सकती है.

(लेखक सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाऊण्टेबिलिटी (सीबीजीए), नई दिल्ली में कार्यरत हैं).

आपदा प्रबंधन...

पृष्ठ 1 का शेष

प्रबंधन प्राधिकरण कुछ ऐसे संगठन हैं, जो आपदा प्रबंधन व्यावसायियों की सेवाएं लेते हैं.

आपदा प्रबंधन में रोज़गार के अवसर व्यापक आकर्षक तथा व्यावसायिक रूप से संतोषजनक हैं. इसलिए आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि आप इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तथा समाज की सेवा करने की इच्छा रखते हैं तो इस क्षेत्र में अवसर तलाशने प्रारंभ कर दें. कई अवसर आपकी प्रतीक्षा में हैं.

कॉलेज तथा पाठ्यक्रम

कॉलेज : उत्तराखंड खुला विश्वविद्यालय, उत्तराखंड
पाठ्यक्रम : आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा.
पात्रता : स्नातक
वेबसाइट : **www.uou.ac.in**

कॉलेज: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय दिल्ली
पाठ्यक्रम: आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा.
पात्रता: स्नातक
वेबसाइट: **www.ignou.ac.in**

कॉलेज: सिम्बियोसिस जैव सूचना विज्ञान संस्थान, पुणे.
पाठ्यक्रम: आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम.
पात्रता: स्नातक
प्रवेश: निजी साक्षात्कार तथा सामूहिक विचार-विमर्श में प्रदर्शन.
वेबसाइट: **www.sig.ac.in**

कॉलेज : डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
पाठ्यक्रम: आपदा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा.
पात्रता: स्नातक
वेबसाइट: **www.dbrau.ac.in**

कॉलेज: संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा
पाठ्यक्रम: आपदा प्रबंधन में एम.बी.ए.
पात्रता: किसी भी विषय में 50% अंक के साथ स्नातक.
प्रवेश: प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन.
वेबसाइट: **http://sangamuniversity.ac.in**

(यह लेख टीएमआईई2ई अकादमी कॅरिअर केंद्र, सिकंदराबाद के सौजन्य से प्राप्त हुआ है.)

शुद्धिपत्र

1. कृपया 103 (I) सीओएमपी पीएल एएससी (एमओडी ''सी'') पिन-905103 मार्फत 99 एपीओ के अंतर्गत मज़दूर के पद के लिए दिनांक 01-07 फरवरी, 2014 के रोज़गार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन संख्या डीएवीपी 10602/11/0124/1314 का अवलोकन करें.
2. रोज़गार समाचार दिनांक 01-07 फरवरी, 2014 के पैराग्राफ 2 में निम्नांकित संशोधन किए गए हैं:
मज़दूर के पदों की संख्या 02-के स्थान पर कृपया मज़दूर के पदों की संख्या 01 पढ़ें.
3. शेष विज्ञापन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

डीएवीपी 10602/11/0142/1314 रो.स. 50/116

सफल उद्यमी बनें

- विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण हेतु, प्रशिक्षण संस्थानों को 100% अनुदान.
- प्रति व्यक्ति प्रति माह रु. 2000/- की वृत्तिका भी.
- हमारी वेबसाइट **www.nhfdc.nic.in** देखें.

नि:शक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
(नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद - 121007

दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स: 0129-2284371
ई-मेल: **nhfdc97@gmail.com**, वेबसाइट : **www.nhfdc.nic.in** रो.स. 50/12

रोज़गार समाचार

श्रुति पाटील
महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
डॉ. ममता रानी
संपादक
नलिनी रानी
संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)
इरशाद अली
(संपादक वितरण)
विनोद कुमार मीणा
संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
पी.के. मंडल
वरिष्ठ कलाकार
के.पी. मणिलाल
लेखा अधिकारी

संपादकीय कार्यालय
रोज़गार समाचार
पूर्वी खण्ड IV तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

ई-मेल-महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
director.employmentnews@gmail.com
विज्ञापन : enewsadvt@yahoo.com

संपादकीय :	: 26163055
विज्ञापन	: 26104284
टेलीफैक्स	: 26193012
वितरण	: 26107405
टैलीफैक्स	: 26175516
प्रोडक्शन	: 26177529
लेखा (विज्ञापन)	: 26193179
लेखा (वितरण)	: 26182079

न्यूज़ डाइजेस्ट

- *प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नेई पाई तॉ, म्यांमार में 4 मार्च 2014 को तीसरे बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लिया. उन्होंने कहा कि भारत बिम्स्टेक सदस्यों के साथ विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि भारत-म्यांमार थाईलैंड त्रिस्तरीय हाईवे, कलाडन मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, एशियाई हाईवे नेटवर्क, आसियान संपर्क मास्टर प्लान और अन्य के जरिए भौतिक संपर्क में सुधार के लिये काम कर रहा है. उन्होंने म्यांमार के लिए एक सीधी नौवहन रेखा की शुरूआत का भी वायदा किया, जिससे क्षेत्र में समुद्री संपर्कों में वृद्धि होगी.*
- *पहली मार्च से उन सात देशों अर्थात अफगानिस्तान, इथियोपिया, सीरिया, केन्या, सोमालिया, नाईजीरिया और पाकिस्तान से अखिल भारतीय दौरे पर आने वाले यात्रियों के लिये यात्रा आरंभ करने से छह सप्ताह पहले पोलियो रोधी दवा (ओपीवी) लेना अनिवार्य हो गया है, जहां अब भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं. इन देशों से भारतीयों को भी दवा पिलाई जायेगी.*
- *चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2014 के लिए कार्यक्रम की घोषणा की. 16वीं लोकसभा के लिये चुनाव, आंध्र प्रदेश, उड़ीशा और सिक्किम विधानसभा चुनावों के साथ नौ विभिन्न चरणों में 7 अप्रैल से 12 मई तक कराए जायेंगे. समूची प्रक्रिया 73 दिनों तक चलेगी. मतगणना 16 मई को होगी.*
- *5 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता, क्या करें और क्या न करें, लागू हो गई. संहिता के तहत मंत्रियों को सरकारी दौरे के साथ चुनाव प्रचार कार्य जोड़ने और चुनाव प्रचार के लिये सरकारी तंत्र के इस्तेमाल तथा सरकारी खर्च पर विज्ञापन देने पर रोक लग गई है. वित्तीय अनुदानों की कोई घोषणा अथवा सड़कों और जलापूर्ति को लेकर कोई वायदा नहीं किया जा सकता है. अधिकारियों के तबादलों पर भी रोक रहेगी.*
- *राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई गई मूल्यांकन प्रणाली को अवैध ठहराते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा-2012 के परिणाम को रद्द कर दिया है और आयोग से ''रॉ मार्क्स'' के आधार पर नये सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे. ये फैसला उच्च न्यायालय की जोधपुर में प्रधान पीठ ने 3 मार्च को सुनाया.*
- *2 मार्च को घोषित ऑस्कर पुरस्कारों में 'ट्वेल्व ईयर्स ए स्लेव' को अमरीकी इतिहास के काले अध्याय के ईमानदार चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिये ऑस्कर पुरस्कार मिला, जबकि अंतरिक्ष पर आधारित थ्री डी फिल्म ग्रेविटी सर्वाधिक सात पुरस्कार लेकर सर्वोच्च स्थान पर रही. पहली बार किसी अश्वेत फिल्म निर्माता को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है. सच्ची घटना पर आधारित फिल्म डैलस बायर्स क्लब मैथ्यू मैकॉनहे के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पाने सहित तीन ऑस्कर पुरस्कार हासिल करने में कामयाब रही, जबकि आस्ट्रेलिया की केट ब्लेनचैट को वूडी एलेन्स ब्लू जैसमिन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है.*

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए **ईरा जोशी,** अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी.21 व 22, सेक्टर.59, नोएडा.201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक.IV, लेवल.5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली.110066 द्वारा प्रकाशित, संपादक: डॉ. ममता रानी